गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 256
दि. 17.01.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

भारत के स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी पर पीएम मोदी का भरोसा, दुनिया में नंबर वन बनने की अपील की

नई दिल्ली, (जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को स्टार्टअप इंडिया के 10 पूरे होने पर भारत के उद्यमियों से अगले 10 साल में इसे दुनियाभर में नंबर वन बनाने की अपील की. इसके साथ, ही उन्होंने एआई को भी पूरी दुनिया में फैलाने की बात कही है. दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्टार्टअप्स से मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च बढ़ाने पर जोर दिया. इस रिपोर्ट में पढ़ें कि स्टार्टअप और एआई से संबंधित कौन-कौन सी बातें कहीं हैं?

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि भारत को अपनी स्टार्टअप कंपनियों की इनोवेशन कैपिसिटी और आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा कि आने वाले 10 साल में देश को वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप रुझानों और तकनीक में नेतृत्व करना चाहिए. 'स्टार्टअप इंडिया' पहल के 10 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से इनोवेशन-ड्रिवन इकॉनमी की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में आगे रहेगा, उसे भविष्य में कंपीटेटिव बढ़त मिलेगी. उन्होंने स्टार्टअप्स से अपील की कि वे एआई समेत उभरती तकनीकों में निवेश बढ़ाएं और दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए समाधान विकसित करें.

कार्यक्रम में मौजूद स्टार्टअप फाउंडर्स और उद्यमियों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि स्टार्टअप सिर्फ कारोबारी मॉडल तक सीमित न रहें, बल्कि नए विचारों, समस्याओं के समाधान और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विकास पर फोकस करें. प्रधानमंत्री ने कहा, 'हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आने वाले 10 सालों में भारत नए स्टार्टअप रुझानों और

तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करे.' उन्होंने दोहराया कि उन्हें देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम, युवाओं के साहस, आत्मविश्वास और नवाचार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि आज किया गया रिसर्च ही भविष्य में बौद्धिक संपदा बनेगा और यही किसी भी देश की असली ताकत होती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों को शुरूआती पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं.

इसके साथ ही, पुराने और अप्रासंगिक नियमों को हटाकर कारोबार को आसान बनाने की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं, ताकि युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में कम से कम समस्या का सामना करना पड़े.

खेल प्रतिभाएं तराशें शिक्षण संस्थान : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

– पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) प्रतियोगिता का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन

– मुख्यमंत्री का आ'ान, किसी एक खेल को गोद लें विश्वविद्यालय-महाविद्यालय

– मुख्यमंत्री योगी ने कहा, खेल गतिविधियों को बढ़ाने से नशे से दूर रहेंगे युवा

– योगी ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश में दिख रही नई खेल संस्कृति

– मैच देखकर बढ़ाया मुख्यमंत्री ने महिला खिलाड़ियों का उत्साह

(जीएनएस)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का आ'ान किया है कि वे किसी एक खेल को गोद लेकर उससे जुड़ी प्रतिभाओं को तराशें। खेल के जरिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराकर अनुशासन और खेल भावना को मजबूत करने में योगदान दें। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) प्रतियोगिता के औपचारिक उद्घाटन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल गतिविधियों को बढ़ाने से युवा नशे से दूर रहेंगे, तमाम विकृतियों से बचे रहेंगे। युवा खेलेगा तो खिलेगा, और यही युवा देश को आगे बढ़ाने में, 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में योगदान देगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने खेलों के माध्यम से भी विकसित भारत बनाने के अभियान में भरपूर प्रयास किए हैं। प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन चुकी है। मेरठ में हर प्रकार के स्पोर्ट्स आइटम बन रहे हैं और इसे सरकार ने ओडीओपी में शामिल किया है।

प्रधानमंत्री मोदी की खेलों में अपार रुचि

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विगत 11 वर्षों में देश में एक नई खेल संस्कृति ने जन्म लिया है। 2014 के पहले खेल की गतिविधियां और प्रतियोगिताएं सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं होती थीं। खेल और खिलाड़ियों की उपेक्षा होती थी।

अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से खिलाड़ी खेल से पलायन करने को विवश होते थे। कुंठित, हताश और निराश रहते थे। जबकि 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खेल और खिलाड़ियों का प्रोत्साहन देखते ही बनता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने खेलो इंडिया, फिट इंडिया और सांसद खेल प्रतियोगिता जैसे अभियानों से स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र की प्रेरणा दी है। गांव-गांव तक खेल प्रतिभाओं को मंच दिया है। प्रधानमंत्री स्वयं विभिन्न खेलों में देश की विजेता टीमों के खिलाड़ियों के साथ बैठते हैं, प्रतियोगिता से पहले भी उनका हौसला बढ़ाते हैं।

महाराष्ट्र निकाय चुनावों में बीजेपी का दबदबा! प्रधानमंत्री मोदी का आया पहला रिएक्शन, जानें जीत पर क्या कहा

(जीएनएस)।

महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 नगर महापालिका के चुनाव में बीजेपी गठबंधन के बहुमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के कार्यकताओं को बधाई दी. पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'मुझे उन सभी एनडीए कार्यकताओं पर गर्व है जिन्होंने महाराष्ट्र में जनता के बीच अथक परिश्रम किया. उन्होंने हमारे गठबंधन के शानदार कामों के बारे में जनता को बताया. साथ ही आने वाले समय के लिए हमारी योजनाओं के बारे में बताया और विपक्ष के झूठ का प्रभावी ढंग से खंडन किया. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं.'

जनता को पसंद आया हमारा कामः पीएम मोदी

पीएम मोदी ने कहा, 'धन्यवाद महाराष्ट्र. राज्य की ऊजार्वान जनता ने एनडीए के सुशासन के एजेंडे को आशीर्वाद दिया है. अलग-अलग नगर निगम चुनावों के परिणाम दशार्ते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के साथ एनडीए का संबंध और भी गहरा हुआ है. विकास को लेकर हमारा कार्य-प्रणाली और दृष्टिकोण जनता को पसंद आया है. महाराष्ट्र भर की जनता के प्रति मेरी कृतज्ञता. यह वोट विकास को गति देने और राज्य की गौरवशाली संस्कृति का जश्न मनाने का प्रतीक है.'

बीजेपी-शिवसेना गठबंधन का दबदबा

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनावों में बीजेपी-शिवसेना गठबंधन का दबदबा देखने को मिला है. नतीजों में महायुति गठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की. हालांकि, इन चुनावों में 'ठाकरे ब्रदर्स' (उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे) को बड़ा झटका लगा है. शिवसेना-यूबीटी और मनसे गठबंधन अधिकतर सीटों पर पिछड़ गया. मुंबई और ठाणे समेत महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों के लिए 15 जनवरी को मतदान हुए. शुक्रवार को नतीजों के आने की शुरूआत हुई और साफ हो गया कि मुंबई का 'किंग' बीजेपी-शिवसेना है.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर बढ़ते जनविश्वास की पुष्टि है बीएमसी चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत : भाजपा

नयी दिल्ली, (जीएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) और महाराष्ट्र के शहरों के नगर निगम चुनावों में महायुति और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को मिली ऐतिहासिक सफलता को पीएम मोदी के नेतृत्व पर जनता के बढ़ते विश्वास की अभिव्यक्ति बताया है। पार्टी के महासचिव तरुण चुघ और प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी नेयह दावा भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में चुनावी नतीजों पर किया। श्री त्रिवेदी ने कहा कि बीएमसी जैसे देश और संभवतः एशिया के सबसे बड़े नगर निगम में भाजपा, महायुती और राजग को मिली प्रचंड जीत यह दशार्ती है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी की स्वीकार्यता लगातार

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय पतंगोत्सव - 2026 को संबोधित किया

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय पतंगोत्सव - 2026 को संबोधित किया। इस अवसर पर दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने देशभर के सभी लोगों, विशेष रूप से किसानों, को मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, माघ बिहू और उत्तरायण की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि उत्तरायण का पर्व पूरे देश में अलग-अलग नामों से मनाया जाता है। यह पर्व इसलिए खुशी का पर्व है क्योंकि हमारा ऋतु चक्र और हमारा जीवन असीम ऊर्जा के स्रोत भगवान सूर्यनारायण पर निर्भर होता है। उन्होंने कहा कि महाकवि कालिदास जी ने भारतवासियों के लिए कहा था - 'उत्सवप्रियाः खलु मनुष्याः', यानी भारत के लोग उत्सवप्रिय होते हैं। हर ऋतु में देश के अलग-अलग हिस्सों में

उत्सवों का आयोजन किया जाता है। हम उत्सवों के माध्यम से पूरे समाज को एकजुट करके आगे बढ़ने की सोच रखते हैं।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि पतंगोत्सव को सतत प्रयासों से और अधिक लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पतंगोत्सव देश की जनता को दिल्ली से जोड़ेगा और आगे चलकर यह पूरे देश का उत्सव बन सकता है। उन्होंने कहा कि पतंगोत्सव को दिल्ली और समूचे देश में विस्तार देने तथा दिल्ली के पतंगोत्सव को इसका केन्द्र बनाने के लिए एक समिति गठित करनी चाहिए, जो इसे लोकप्रिय बनाने और इसमें जनभागीदारी बढ़ाने के पहलुओं पर काम करे। उन्होंने कहा कि अगला पतंगोत्सव ऐसा हो जिससे इस उत्सव का स्थान देश और दुनिया के प्रमुख पतंगोत्सवों में अग्रणी स्थानों में शामिल हो।

श्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली में देश के अलग-अलग किस्मों के बाँस से सुसज्जित सुंदर प्राकृतिक स्थान बाँसेरा पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है।

उन्होंने कहा कि यह उद्यान इस बात का परिचायक है कि यदि कोई व्यक्ति अपने संकल्प को जमीन पर उतारने के लिए कृतनिश्चयी हो जाए, तो कैसे शानदार परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि बांसेरा उद्यान का उपयोग बढ़ाने के लिए तथा दिल्ली के लोगों को इसकी ओर आकर्षित करने के लिए दिल्ली सरकार को यहाँ अच्छे आयोजन करने की आवश्यकता है।

इंदौर में दूषित पानी से 24 मौतें! राहुल गांधी करेंगे पीड़ित परिवारों से मुलाकात, जीतू पटवारी का बड़ा दावा

(जीएनएस)।

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। इस खुलासे के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सीधे तौर पर राज्य सरकार और नगर निगम की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया है। जीतू पटवारी ने कहा कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि सिस्टम की असफलता का परिणाम है, जिसमें आम नागरिकों की जान चली गई।

राहुल गांधी इंदौर पहुंचेंगे, पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात

दूषित जलकांड को लेकर कांग्रेस ने इसे मानवीय संकट बताया है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर दौरे पर आ रहे हैं। वे अस्पतालों में भर्ती मरीजों और दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हालचाल जानेंगे और उन्हें संबल प्रदान करेंगे।

जीतू पटवारी ने कहा, "जब सरकार आंख मूंदे बैठी है, तब कांग्रेस पीड़ितों के साथ खड़ी है। राहुल गांधी स्वयं इंदौर आकर हालात का जायजा लेंगे और पीड़ित परिवारों की पीड़ा सुनेंगे।"

कांग्रेस का आरोपः चेतावनी के बावजूद नहीं सुधारी गई व्यवस्था

कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि इंदौर के कई इलाकों में लंबे समय से दूषित पानी की शिकायतें मिल रही थीं। स्थानीय नागरिकों ने जलापूर्ति को लेकर बार-बार शिकायतें कीं, लेकिन नगर निगम और प्रशासन ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसका नतीजा यह हुआ कि लोग गंभीर रूप से बीमार हुए और कई की जान चली गई।

पटवारी ने कहा कि यह केवल इंदौर का मामला नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में पेयजल व्यवस्था बदहाल है। कहीं नल सूखे हैं, तो कहीं जहर मिला पानी लोगों को परोसा जा रहा है।

"हर नागरिक को सुरक्षित पानी मिले, यही हमारी लड़ाई"

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा कि स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगी और सड़क से लेकर सदन तक सरकार को जवाबदेह बनाएगी।

उन्होंने कहा कि इंदौर के इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो कांग्रेस आंदोलन करेगी और न्याय के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

राहुल गांधी का 17 जनवरी का पूरा कार्यक्रम

सुबह 9:30 बजे - दिल्ली से रवाना

11:00 बजे - स्पेशल फ्लाइट से इंदौर एयरपोर्ट आगमन

11:15 बजे - एयरपोर्ट से बॉम्बे हॉस्पिटल के लिए रवाना

11:45 से 12:15 बजे - अस्पताल में भर्ती मरीजों व परिजनों से मुलाकात

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

सेवा, संकल्प और संघर्ष का प्रतीक बना लखनऊ का भव्य भंडारा– यूथ ब्यूरो ने मकर संक्रांति पर दिखाई जनसेवा की असली ताकत

लखनऊ । एंटी क्राइम एंटी करप्शन मिशन भारत ट्रस्ट यूथ ब्यूरो के तत्वाधान में मकर संक्रांति के पावन अवसर पर लखनऊ में एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। यह आयोजन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सेवा पहुँचाने का मजबूत संकल्प था राष्ट्रीय अध्यक्ष सुयश श्रीवास्तव के सशक्त नेतृत्व में आयोजित इस भंडारे में सैकड़ों जरूरतमंदों को सम्मानपूर्वक भोजन कराया गया। यूथ ब्यूरो की पूरी टीम ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि सेवा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर किया गया संघर्ष है।

कार्यक्रम में विशेष रूप से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हर्षित श्रीवास्तव,राष्ट्रीय सचिव आकाश श्रीवास्तव,प्रदेश अध्यक्ष आभाष श्रीवास्तव,प्रदेश उपाध्यक्ष प्रतीक सिंह,प्रदेश सचिव संजोली गोस्वामी की गरिमामयी उपस्थिति रही। सभी पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय अध्यक्ष सुयश श्रीवास्तव ने कहा कि 'यूथ ब्यूरो का लक्ष्य केवल अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ही नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए निरंतर सेवा कार्य करना है। मकर संक्रांति जैसे पर्व हमें आपसी भाईचारे और मानवता की याद दिलाते हैं।' यह भव्य भंडारा आयोजन यूथ ब्यूरो की सेवा भावना, संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण बना। संगठन ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे जनसेवा कार्यक्रम और अधिक व्यापक स्तर पर किए जाएंगे।

सम्पादकीय

जनता को केंद्र में रखना लोकतंत्र की सफलता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रमंडल के लगभग 50 देशों के पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र इसलिए सफल है क्योंकि शासन के वेंद्र में जनता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह विचार शत प्रतिशत सही है। लोकतंत्र का मतलब जो राजनीति शास्त्र में बताया गया है, वह आज भी दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिकन के इसी सूत्र वाक्य के निकट परिव्रमा लगाता है कि "लोकतंत्र जनता द्वारा, जनता का और जनता के लिए होता है।" प्रधानमंत्री ने भी यही कहा कि भारत का लोकतंत्र इसलिए सफल है क्योंकि जनता शासन के वेंद्र में है। मतलब कि सरकार 'जनता के लिए' ही हर काम करती है। यही नहीं भारत में आज यदि लोकतंत्र का झंडा बुलंद है तो इसका श्रेय मात्र जनता को जाता है जिसने न सिर्प भारत के गुलामी की जंजीरों को तोड़ा बल्कि धैर्य, समझ और अपने अर्जित अनुभवों से लोकतंत्र पर आने वाले हर संकट को निष्फल कर दिया है।

भारत में शासन जनाकांक्षाओं के अनुरूप ही चलता है। आज सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है, वे सभी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही चलाईं जा रही हैं। सच तो यह है कि जिस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया उसमें राष्ट्रमंडल के ऐसे देश भी शामिल हैं जिनकी जनता को लोकतंत्र का उतना अच्छा अनुभव नहीं है जितना कि भारत की जनता को है। इसलिए प्रधानमंत्री ने देश की जनता को ही लोकतंत्र की सफलता के लिए न सिर्प श्रेय दिया है बल्कि उन्होंने तो यहां तक कहा कि सरकार अपनी हर योजना की सफलता का कारण मात्र जनता को वेंद्रित किए जाने की वजह से ही योजनाएं भी सफल हो रही हैं और जिस देश में योजनाओं का लाभ आम जनता को मिलता है उस देश के लोकतंत्र को किसी से कोई चुनौती नहीं मिल सकती।

सच तो यह है कि बृहस्पतिवार को राष्ट्रमंडल देशों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता की भूमिका और जनभावनाओं के अनुवूल शासन की योजनाओं की तरफ इशारा करके प्रतिनिधियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत में लोकतंत्र सफल है और इसके लिए न सिर्प देश की जनता की वर्षों तक की गई तपस्या को श्रेय जाता है बल्कि भारतीय संविधान में प्रदत्त नीति-निर्देशक तत्वों को भी श्रेय जाता है जिनकी वजह से ही सरकारें जनाकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करने का न मात्र संकल्प करती हैं बल्कि देश की जनता भी सरकार को जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए विवश भी करती है। स्पष्ट रूप से सरकारें अपनी लोकप्रियता साबित करने के लिए यदि जनकल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं तो जनता भी मात्र उन्हें ही सत्ता में बने रहने देती है जो जनता के लिए लोक कल्याण के उद्देश्यों के लिए कार्य करती हैं। बहरहाल जिन देश की सरकारें अपनी जनता को वेंद्र में न रखकर शासन करने की गलती करती हैं, उन देशों में जनाव्रोश, उथल-पुथल और हिसक व झड़प की घटनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे देशों की सरकारें जनान्दोलन से हटाईं जाती हैं। वुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल के उन सदस्य देशों को इस बात की नसीहत दी कि जनता ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है, जो खुद को जनता से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं या जो शक्ति के आधार पर शासन चलाने की गलती करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने भावनगर में 107 दिव्यांगजनों को 1.16 करोड़ रुपए की साधन सहायता का वितरण किया

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडिप योजना तथा जेटको और पीजीवीसीएल के सीएसआर कार्यक्रम के तहत एलिम्को निःशुल्क दिव्यांग उपकरण सहायता वितरण कैंप आयोजित

राज्य सरकार ने गत पांच वर्षों में 4 लाख से अधिक दिव्यांगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर ८20 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगजनों के कल्याण की दिशा में बड़ा काम किया
- दिव्यांगजनों के लिए वरदान बने दिव्याशा केंद्र
- दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए गांधीनगर में 316 करोड़ रुपए के खर्च से एथलीट्स हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर का निर्माण हो रहा है, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय खेलों में अधिक मेडल जीत सकें
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'सशक्त दिव्यांगजन यानी सशक्त भारत' विजन के साथ गत 10 वर्षों में दिव्यांग कल्याण योजनाओं के खर्च में तीन गुना वृद्धि हुई

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में अनेक क्रांतिकारी बदलाव आए हैं : केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया

श्री नरेन्द्र मोदी ने दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में लाने की संवेदनशील पहल की : कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी

गांधीनगर, 16 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को भावनगर में दिव्यांग उपकरण सहायता वितरण शिविर के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने दिव्यांगों का जीवन आसान और उन्नत बनाने के लिए

दिव्यांगजनों के हित में अनेक निर्णय किए हैं।

भावनगर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की दिव्यांगजनों के लिए सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग की सहायता योजना (एडिप योजना) और गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेटको) और पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल) के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के अंतर्गत एलिम्को और भावनगर जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क दिव्यांग साधन-उपकरण सहायता वितरण कैंप का आयोजन किया गया।

मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से एक ही दिन में एक साथ 1017 दिव्यांगजनों को 1.16 करोड़ रुपए की साधन सहायता वितरित करने के इस कार्यक्रम को दिव्यांग कल्याण की सरकार की प्रतिबद्धता करार दिया।

मुख्यमंत्री ने भावनगर और बोटाद जिले में 15 दिनों तक कैंप आयोजित कर 2600 से अधिक दिव्यांगजनों को 3.51 करोड़ रुपए के 4800 से अधिक साधनों का निःशुल्क वितरण कर उनकी आत्मनिर्भरता का अहम कार्य करने के लिए केंद्रीय मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया और उनकी टीम को बधाई दी। इसके अलावा, उन्होंने राज्य के दो सार्वजनिक उपक्रमों जेटको और पीजीवीसीएल की भी सीएसआर के तहत इस साधन वितरण में योगदान देने के लिए सराहना की।

इस अवसर पर मुख्मयंत्री ने कहा कि गुजरात में पिछले पांच वर्ष में 4 लाख से अधिक दिव्यांगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कर 820 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई है। इतना ही नहीं, दिव्यांगों को प्रमाण पत्र के लिए बार-बार मेडिकल चेकअप कराने की मुश्किलों से भी मुक्ति मिली है। दिव्यांगता प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य करने के निर्णय से दिव्यांगों को बड़ी राहत प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि अब 60 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दृष्टिबाधितों को संत सूरदास योजना का लाभ दिया जाता है। ऐसे योजनाओं का लाभ आसानी से मिलने के कारण दिव्यांगजन आत्मसम्मान से जीवन जी रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में दिव्यांगों का जीवन बदला और उन्हें नए अवसर प्रदान किए हैं, इस बात का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुगम्य भारत अभियान के जरिए दिव्यांगजनों के कल्याण की दिशा में बड़ा कार्य किया है। इस अभियान के कारण देश में सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सार्वजनिक स्थानों पर दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं स्थापित की गई हैं और ईज ऑफ लिविंग से उनका जीवन आसान बना है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की 'प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र' के निर्माण की पहल की चर्चा करते हुए कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 300 दिव्याशा केंद्र बनाने का लक्ष्य है, जिनमें से 100 तो कार्यरत हो चुके हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों की प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकाकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए भी श्री मोदी ने योजनाबद्ध कार्यपद्धति अपनाई है। इस बारे में उन्होंने कहा कि गांधीनगर में 316 कोरड़ रुपए की लागत से पैरा एथलीटों के लिए हाई परफॉर्मेंस स्पोटर्स सेंटर का निर्माण हो रहा है। इस सेंटर में हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा कि वे आने वाले समय में आयोजित होने वाले विश्व स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक मेडल जीत सकें।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प में दिव्यांगजनों के शिक्षा, रोजगार, टेक्नोलॉजी और उद्योगों में समान भागीदार बनाने की मंशा व्यक्त की।

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्रीमती निमुबेन बांभणिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में अनेक क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। दिव्यांगजनों के लिए सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू हैं। बोटाद और भावनगर जिले में लगभग 2700 दिव्यांगजनों का परीक्षण किया गया था। भावनगर जिले में शिहोर और पालीताणा तथा बोटाद जिले में तीन कैंप सफलतापूर्वक आयोजित किए गए, जिनमें 825 दिव्यांगजनों को कुल 121.20 लाख रुपए मूल्य के 1577 साधन वितरित किए गए।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार दिव्यांगजनों को 'आत्मनिर्भर' बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। एडिप योजना के तहत लाखों दिव्यांगजनों को निःशुल्क आधुनिक सहायक साधन दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि गत 11 वर्षों में दिव्यांगजनों को साधन-सहायता के लिए लगभग 18 हजार से अधिक कैंपों का आयोजन कर 31 लाख से अधिक दिव्यांगजनों तक सहायता पहुंचाई गई है।

कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने कहा कि 'दिव्यांग' शब्द की भावनात्मक अभिव्यक्ति और दिव्यांगजनों के लिए व्यवस्थाओं की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिव्यांगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए जो संवेदनशील पहले की थी, उसका फल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। दिव्यांग साधन सहायता कार्यक्रमों के जरिए अनेक लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी विनम्रता, निष्कपटता और संवेदनशील कार्य शैली के माध्यम से गुजरात में एक मजबूत नेतृत्व स्थापित किया है। उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम समाज के लिए प्रेरणादायी बना है। उन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की जा रही पहलों की प्रशंसा की।

श्री वाघाणी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां सीएसआर फंड का उचित उपयोग समाज के हित में करने के लिए आगे आ रही हैं। दिव्यांगजनों को साधन सहायता मिलने से वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं और समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का शुभकामना संदेश पढ़ा गया।

भावनगर कलेक्टर डॉ. मनीष कुमार बंसल ने स्वागत भाषण दिया जबकि जिला विकास अधिकारी श्री हनुल चौधरी ने आभार व्यक्त किया। एलिम्को कंपनी के महाप्रबंधक श्री विवेक द्विवेदी ने कार्यक्रम की रूपरेखा देते हुए अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर भावनगर के प्रभारी मंत्री श्री कौशिकभाई वेकरिया, महापौर श्री भरतभाई बारड़, मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री राजूभाई राबड़िया, उप महापौर श्रीमती मोनाबेन पारेख, विधायक सर्वश्री सेजलबेन पंड्या, भीखाभाई बारैया, शंभुनाथ टुंडिया, गौतमभाई चौहाण, शिवाभाई गोहिल, केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री रवि शंकर, अग्रणी श्री कुमारभाई शाह और दिग्विजयसिंह गोहिल सहित कई अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।

अमरीन शहजाद अब्राहानी कौन हैं? अरुन गवली की डैडी विरासत की नींव हिलाई, बेटी गीता की बजाई सीटी

(जीएनएस)।

मुंबई की बीएमसी चुनाव 2026 ने कई पुरानी राजनीतिक विरासतों को चुनौती दी, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा अरुण गवली (डॉन 'डैडी') के परिवार को। गैंगस्टर से नेता बने गवली की दोनों बेटियां - गीता गवली और योगिता गवली - हार गईं। गीता गवली को वार्ड 212 (बायकुला-अग्रीपाडा) में समाजवादी पार्टी (एसपी) की अमरीन शहजाद अब्राहानी ने हराया, जबकि योगिता को वार्ड 207 में बीजेपी के रोहिदास लोखंडे ने शिकस्त दी।

यह डबल हार गवली परिवार के घटते राजनीतिक प्रभाव का प्रतीक है, जहां 'डैडी' की पुरानी पकड़ अब कमजोर पड़ रही है। आइए हम जानते हैं आखिर कौन है अमरीन शहजाद अब्राहानी? उनकी जीत की वजह, गवली परिवार की हार और बायकुला की सियासत को विस्तार से समझेंगे...

अमरीन शहजाद अब्राहानी?

अमरीन शहजाद अब्राहानी समाजवादी पार्टी की एक उभरती हुई नेता हैं, जो मुंबई के वार्ड 212 (बायकुला-अग्रीपाडा क्षेत्र, महिलाओं के लिए आरक्षित) से बीएमसी चुनाव 2026 में उम्मीदवार थीं। वे खुद को 'मां, पत्नी और सोशल वर्कर' बताती हैं। उनके पति शहजाद यूसुफ अब्राहानी हैं, और वे मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हैं।

सोशल मीडिया प्रोफाइलः इंस्टाग्राम पर @amrnsabrahani हैं, जहां उनके 8.7K+ फॉलोअर्स और 49+ पोस्ट हैं। वे सोशल वर्क, लोकल इश्यूज (जैसे हेल्थ, गिग वर्कर्स की समस्याएं, डिलीवरी के दौरान प्राइवेट हॉस्पिटल्स की महंगाई) पर फोकस करती हैं। कैम्पेन में वे 'वार्ड 212 के हर कोने के लिए जिम्मेदारी' का नारा देती रहीं।

पॉलिटिकल स्टाइलः अमरीन एक नई फेस हैं, जो पुरानी विरासत (जैसे गवली फैमिली) के खिलाफ 'बदलाव' और 'डेवलपमेंट' पर जोर देती हैं। उन्होंने चुनाव से पहले कहा कि लोग अब 'लीगेसी' नहीं, बल्कि 'वर्क' देखते हैं। उनकी जीत को मुस्लिम-बहुल इलाके में एसपी की मजबूती का संकेत माना जा रहा है।

पार्टीः समाजवादी पार्टी (एसपी), जो मुंबई में मुस्लिम और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर फोकस करती है।

अमरीन की जीत को 'नई पीढ़ी ५२ पुरानी विरासत' की लड़ाई माना जा रहा है, जहां उन्होंने गवली की बेटी को हराकर साबित किया कि बायकुला अब बदलाव चाहता है।

इटउ 2026 हं१ि 212 एॅी३ङ्कल्लः गीता गवली ५२ अमरीन शहजाद अब्राहानी

वार्ड 212 (बायकुला-अग्रीपाडा) गवली परिवार का गढ़ रहा है। गीता गवली (उम्र 42 वर्ष, अखिल भारतीय सेना - ABHS) तीन बार की पूर्व पार्षद थीं और 2017 में इसी वार्ड से जीती थीं। उन्होंने 'डॉन की बेटियां नहीं, डैडी की बेटियां' का नारा दिया, कहते हुए कि लोग अरुण गवली को 'डैडी' कहकर प्यार करते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं।

लेकिन अमरीन शहजाद अब्राहानी ने उन्हें हराकर बड़ा उलटफेर किया।

अन्य उम्मीदवारः-

नाजिया सिद्दीकी (कांग्रेस)

श्रावणी विनय हल्दानकर (एमएनएस)

स्मिता संतोष साल्वी (संभाजी ब्रिगेड पार्टी)

मुस्कान मेराज शेख (स्वतंत्र)

जीत की वजहेंः

लोकल इश्यूज पर फोकसः अमरीन ने हेल्थ, गिग वर्कर्स (जैसे ZomÔto, Swiggy डिलीवरी बॉयज), पब्लिक फैसिलिटीज और डेवलपमेंट पर जोर दिया। गवली फैमिली की पुरानी 'लीगेसी' अब वोटर्स को प्रभावित नहीं कर पाई।

समुदाय समर्थनः बायकुला में मुस्लिम बहुल इलाकों में एसपी की पकड़ मजबूत रही। अमरीन की 'सोशल वर्कर' इमेज ने युवा और महिलाओं को आकर्षित किया।

गवली फैमिली की कमजोरीः अरुण गवली की जेल (17 साल) और राजनीतिक गिरावट ने प्रभाव कम किया। गीता की संपत्ति ₹7.26 करोड़ घोषित थी, लेकिन वोटर्स ने 'बदलाव' चुना।

यह जीत गवली परिवार के लिए डबल झटका थी, क्योंकि योगिता भी वार्ड 207 में हार गईं।

विरासतः से राजनीति तक का सफर

अरुण गवली (अरुण गवली) 1970-80 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे। वे 'बायकुला कंपनी' गिरोह के लीडर बने, दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी रही। 1980 में बालासाहेब ठाकरे का संरक्षण मिला, लेकिन बाद में मतभेद हो गए।

पॉलिटिकल करियरः 2004-2009 तक चिंचपोकली से विधायक रहे। अपनी पार्टी अखिल भारतीय सेना बनाई।

जेल और रिहाईः 2008 में शिवसेना पार्षद की हत्या के केस में 17 साल जेल में रहे। सितंबर 2025 में जमानत पर रिहा।

परिवारः बेटियां गीता और योगिता राजनीति में सक्रिय रहीं, लेकिन 2026 में दोनों हार गईं। यह उनकी विरासत पर बड़ा सवाल है।

समर्थक उन्हें 'डैडी' कहते हैं, क्योंकि उन्होंने गदड़ी चॉल में लोगों की मदद की, लेकिन अब इलाका बदलाव चाहता है।

क्यों हारी गवली, क्यों जीती अमरीन?-डीप एनालिसिस

नीचे टेबल में मुख्य फैक्टर्सः-

क्रमांक फैक्टर गीता गवली (हार) अमरीन शहजाद अब्राहानी (जीत) प्रभाव

1 पृष्ठभूमि पूर्व पार्षद, गवली परिवार की बेटी सोशल वर्कर, नई फेस, एसपी उम्मीदवार पुरानी विरासत ५२ नया बदलाव

नारा "डैडी की बेटियां", लोकल मदद "डेवलपमेंट और जिम्मेदारी" वोटर्स ने बदलाव चुना

3 समुदाय गवली का पुराना आधार मुस्लिम-बहुल इलाके में एसपी सपोर्ट एसपी की मजबूती

4 इश्यूज लीगेसी पर फोकस हेल्थ, गिग वर्कर्स, पब्लिक सुविधाएं लोकल प्रॉब्लम्स पर जीत

5 परिणाम हार (वार्ड 212) जीत (वार्ड 212) गवली प्रभाव कमजोर

इनसाइटः बायकुला अब 'लीगेसी' से ज्यादा 'परफॉर्मेंस' देखता है। अमरीन की जीत एसपी की मुंबई में वापसी का संकेत है, जबकि गवली परिवार की हार अंडरवर्ल्ड से राजनीति की सीमा दिखाती है।

बीएमसी 2026 का सबक

अमरीन शहजाद अब्राहानी की जीत ने साबित किया कि मुंबई की सियासत में नई आवाजें पुरानी विरासतों को चुनौती दे सकती हैं। गवली परिवार का 'डैडी' प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है, जबकि अमरीन जैसे सोशल वर्कर्स आगे आ रहे हैं। यह चुनाव लोकल इश्यूज और बदलाव की जीत है।

राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मान में भोज का आयोजन

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मान में भोज आयोजित किया

श्री राधाकृष्णन ने कहा - विविध विचारों के बीच शालीनता और गरिमापूर्ण संवाद और चर्चा, साझा और प्राथमिक दायित व

श्री राधाकृष णन ने कहा - राष्ट्रमंडल देशों की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति और ऐतिहासिक अनुभव भिन्न; फिर भी वे समान संसदीय लोकाचार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों और मूल्यों की सामूहिक प्रतिबद्धता से बंधे हैं

श्री राधाकृष्णन ने कहा - पीठासीन अधिकारी विधानमंडलों की गरिमा और लोगों की आवाज के अंतिम संरक्षक

(जीएनएस)।

राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति श्री सी.पी.राधाकृ णन ने आज नई दिल्ली के संविधान सदन में राष्ट्रमंडल देशों के संसदीय अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मान में भोज आयोजित किया। 14 से 16 जनवरी, 2026 तक भारत में राष्ट्रमंडल संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन के दौरान भोज आयोजित किया गया।

सभापति ने भारत के ऐतिहासिक संसद भवन के संविधान सदन में पीठासीन अधिकारियों और संसदीय अध्यक्षों की मेजबानी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह भवन साढ़े सात दशकों से अधिक समय से भारत के जीवंत और समृद्ध संसदीय लोकतंत्र का प्रतीक है।

श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल लोकतंत्रों को एकजुट करने वाले सामूहिक सद्भाव और साझा उद्देश्य की भावना दशार्ता है। श्री राधाकृ णन ने भारत की सभ्यतागत विचारधारा से प्रेरित संवाद, सहयोग और पारस्परिक सम्मान द्वारा एक साथ आगे बढ़ने के महत्व पर बल दिया।

संसदीय अध्यक्षों और पीठासीन संवैधानिक अधिकारियों की भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री राधाकृष्णन ने विचारों की विविधता के बीच शालीनता और गरिमा के साथ बहस, संवाद और चर्चा को सुगम बनाने की साझा और प्राथमिक उत तरदायित व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल देशों की भौगोलिक स्थिति, संस्कृति और ऐतिहासिक अनुभव भिन्न हैं, फिर भी वे समान संसदीय लोकाचार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता से बंधे हैं।

श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पीठासीन अधिकारी विधायिका की गरिमा और लोगों की आकांक्षापूर्ण आवाज के अंतिम संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें लोकतंत्र के पवित्र सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यवस्थित आचरण के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया है।

भारत की लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। उन्होंने कहा कि भारत राष्ट्रमंडल को केवल ऐतिहासिक संगठन नहीं, बल्कि समान साझेदारों के बीच सहयोग के अहम और भविष्योन्मुखी मंच के तौर पर देखता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रमंडल संसदीय अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन - सीएसपीओसी जैसे मंच संस्थागत ज्ञान, सर्वोत्तम प्रचलन और अनुभवों को साझा करने के बहुमूल्य अवसर प्रदान करते हैं।

श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस प्रकार के आदान-प्रदान से विधानमंडलों की स्थिति अनुकूलता, पारदर्शिता और समावेशिता बढ़ाकर उन्हें सुदृढ़ करने में योगदान मिलता है। सहभोजन या सामुदायिक भोजन की परंपरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने समानता, बंधुत्व और नाते को बढ़ावा देने में इसके प्रतीकात्मक महत्व की चर्चा की।

उन्होंने संस्कृत प्रार्थना "समस्थ लोकाः सुखिनो भवन्तु" - यानी सभी प्राणी सर्वत्र सुखी और स्वतंत्र हों - का आ'ान करते हुए साझा प्रयासों द्वारा अपने लोगों के कल्याण और समृद्धि के लिए अथक प्रयास करने की राष्ट्रमंडल विधानमंडलों की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

श्री राधाकृ णन ने विश्वास व्यक्त किया कि सीएसपीओसी 2026 के दौरान होने वाली चर्चा से राष्ट्रमंडल देशों के बीच संसदीय संबंध, आपसी समझ और सहयोग और भी सुदृढ़ होंगे।

संबोधन के समापन में उन्होंने भारत आने वाले गणमान्य अतिथियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि उनकी भारत यात्रा सफल और स्मरणीय रहेगी।

कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्यसभा उपसभापति श्री हरिवंश, अंतर-संसदीय संघ की अध्यक्ष डॉ. तुलिया एकसन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के अध्यक्ष डॉ. क्रिस्टोफर कलीला, राज्यसभा और लोकसभा के महासचिव और राष्ट्रमंडल के विभिन्न देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया।

'पिया बिना ससुराल', तलाक के बाद मातोश्री में क्यों रहती है ठाकरे खानदान की ये बहू?

(जीएनएस)।

मुंबई पर 25 सालों से उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना का कब्जा था, लेकिन इस बार बीजेपी गठबंधन ने इस पर अपना अधिकार जमा लिया है। निकाय चुनावों में जनता का प्यार और आशीर्वाद उसे ही मिला है, ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए काफी अहम था और उन्हें लगता था कि वो 'मराठी-मानुष' मुद्दे से जनता के दिलों में जगह बना लेंगे और इसी के चलते उन्होंने वो कदम भी उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, जीं हां यहां जिक्र हो रहा है राज ठाकरे से पैचअप का।

20 साल बाद दोनों भाईयों के बीच की कड़वाहट कम हुई और दोनों ने एक मंच पर आकर जनता के बीच मुंबई, मराठी और मानुष का संदेश देने की कोशिश की लेकिन ये संदेश जनता को समझ नहीं आया और आज दोनों ब्रदर्स चुनावी संग्राम में फेल हो गए। बीजेपी का कहना है कि ये गठबंधन मौसमी था और अब ये हार चुका है तो चुनाव के बाद फिर से टूट जाएगा। अब वो कितना सही साबित होते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन आपको यहां पर ठाकरे खानदान के बारे में एक अनोखी बातें बताते है।

गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे की बड़ी भाभी स्मिता ठाकरे अपने तलाक के बाद भी 'मातोश्री' (ठाकरे के घर का नाम) में ही रहती हैं। हैरत हुई ना, लेकिन सच यही है। दरअसल इसके पीछे एक दर्दनाक कहानी है, आपको बता दें कि शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के तीन पुत्र थे। उनके बड़े बेटे का नाम बिंदु माधव था,जिनकी दुर्भाग्यवश एक हादसे में मौत हो गई थी।

उनके मझले बेटे का नाम जयदेव ठाकरे था, जिनके विचार बाला साहेब से बिल्कल उलट थे इसी वजह से उनकी पिता से बनती नहीं थी। उन्होंने तीन शादियां की थी। उनका पहला विवाह जयश्री कालेकर से हुआ था लेकिन कुछ वक्त बाद उनका जयश्री को तलाक हो गया था, कहते हैं कि इसी तलाक के बाद बाला साहेब और बेटे के बीच गहरा तनाव था।

बाला साहेब ने बेटे को घर से निकाला

जयदेव ने दूसरी शादी मुंबई में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली-बढ़ी स्मिता ठाकरे से की, ये प्रेम विवाह था लेकिन स्मिता ने जल्द ही अपने मधुर व्यवहार से पूरे परिवार का मन मोह लिया।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

अहमदाबाद-मुंबई रूट पर 250किमी. की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत, लॉन्च डेट से लेकर डेडलाइन पर अपडेट

(जीएनएस)।

भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी परियोजना वंदे भारत ट्रेन के नेटवर्क का लगातार विस्तार हो रहा है। रेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है कि साल 2027 में वंदे भारत ट्रेन का नया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस वर्जन 4.0 लॉन्च किया जाएगा। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह रेलवे ट्रैक पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होगी। इसके साथ ही यह भारत की अब तक की सबसे तेज ट्रेन बन जाएगी।

रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, वंदे भारत 4.0 की पहली सेवा अहमदाबाद से मुंबई के बीच शुरू की जाएगी। इस रूट को हाई-स्पीड ट्रेनों के लिए तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जा रहा है। इससे अगले वर्जन की वंदे भारत ट्रेनों का संचालन सुरक्षित तरीके से होगा।

350 तक की स्पीड से दौड़ेगी ट्रेन

रेलवे एक्सपर्ट और वंदे भारत परियोजना से जुड़े सुधांशु मणि ने बताया कि वंदे भारत 4.0 को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर

डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन बेहतर क्वालिटी स्टैंडर्ड, अत्याधुनिक डअश्अउल्ल 5.0 सुरक्षा प्रणाली और हाई-स्पीड कॉरिडोर से लैस होगी। इसे तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने की योजना ध्यान में रखकर बनाया गया है। भविष्य में 350 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति वाले कॉरिडोर पर भी चलाया जा सकेगा।

2019 में शुरू हुई थी पहली वंदे भारत ट्रेन

वंदे भारत ट्रेनों की यात्रा 15 फरवरी 2019 से शुरू हुई थी। इसके बाद 2022 में वंदे भारत 2.0 और 2025 में 3.0 वर्जन ऑपरेशनल हुआ। साल 2026 में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लॉन्च की जा चुकी है, जिससे लंबी दूरी की रातभर की यात्राएं ज्यादा आरामदायक बनेंगी। तेज रफ्तार, आधुनिक सुरक्षा तकनीक और बेहतर आराम के कारण वंदे भारत ट्रेनें यात्रियों की पहली पसंद बनती जा रही हैं और भारत की इंटर-सिटी रेल यात्रा को पूरी तरह बदलने की दिशा में बढ़ रही है।

4500 वंदे भारत चलाने की योजना

- दिसंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार 164 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं।

- यह ट्रेनें देश के 274 जिलों को कवर करती हैं और यात्रियों को आरामदायक सफर का अनुभव मिलता है।

- जल्द ही गुवाहाटी और कोलकाता के बीच पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने वाली है, जो लंबी दूरी की यात्रा को और आरामदायक बनाएगी।

- रेलवे का लक्ष्य 2030 तक 800 वंदे भारत ट्रेनें चलाने और 2047 तक 4500 तक पहुंचाने का है।

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप पे चर्चा कार्यक्रम में भारतीय युवाओं में बढ़ते आत्मविश्वास का उल्लेख किया

श्री पीयूष गोयल ने कहा - प्रौद्योगिकी-आधारित स्टार्टअप पर्यटन और कौशल विकास में व्यापक बदलाव ला सकते हैं

श्री गोयल ने कहा - भारतीय स्टार्टअप के लिए मुक्त व्यापार समझौते वैश्विक अवसर खोल रहे हैं, उन- होंने स्टार्टअप और लघु उद्यमों को साथ लाकर सुदृढ़ घरेलू आपूर्ति श्रृंखला निर्माण पर जोर दिया

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप पे चर्चा संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नए और उभरते भारत में सबसे स्पष्ट बदलाव देश के युवाओं में बढ़ता आत्मविश्वास है। उन्होंने कहा कि आज के युवा जोखिम उठाने, उद्यमशीलता अपनाने और नए विचारों पर काम करने को अत्यंत इच्छुक हैं। यह करियर विकल्पों को लेकर पहले जो झिझक थी उसमें उल्लेखनीय परिवर्तन का संकेत है। श्री गोयल ने कहा कि यह आत्मविश्वास नवाचार और भविष्योन्मुखी विकास के प्रति भारत की मानसिकता में मूलभूत बदलाव को दर्शाता है।

श्री गोयल ने संवाद के दौरान, कई व्यवसायिक संस्थापकों और सफल उद्यमियों से बातचीत की। उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों के सवाल पर श्री गोयल ने पर्यटन और कौशल विकास को चिन्हित किया। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र राष्ट्रीय आवश्यकताओं और उद्यमशीलता दोनों में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी आबादी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने में इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को समेकित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए देश में कार्यबल तैयार करने हेतु प्रशिक्षण, पुनः

प्रशिक्षण और दोबारा कौशल विकास के महत्व पर बल दिया।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने मुक्त व्यापार समझौतों-एफटीए के बारे में कहा कि दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के हाल के समझौते स्टार्टअप और उद्यमियों को महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इन समझौतों से निवेशकों में निश्चितता और विश्वास उत्पन्न होगा साथ ही भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए नए बाजार खुलेंगे। उन्होंने स्टार्टअप्स को निवेश आकर्षित करने और वैश्विक विस्तार के लिए विदेशों के साथ स्टार्टअप-टू-स्टार्टअप सहयोग और साझेदारी तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री गोयल ने सेवा, गतिशीलता, भुगतान, संवहनीयता, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अवसरों की चर्चा की।

डीप-टेक इनोवेशन (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स और एडवांस्ड मैटेरियल्स इत्यादि) पर श्री गोयल ने पूरे देश में हो रही प्रगति पर संतोष और आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हाल की नीतिगत चर्चाओं में डीप-टेक विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित हुआ है और सरकार द्वारा घोषित 10 हजार करोड़ रुपये के दूसरे स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स से डीप-टेक स्टार्टअप्स, विशेष रूप से इनके विकास के शुरूआती और महत्वपूर्ण चरणों में काफी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि देशभर के इनक्यूबेटरों (स्टार्टअप्स के लिए ऐसा केंद्र जो शुरूआती चरण के व्यवसायों को ऑफिस स्पेस, मार्गदर्शन, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है) और शैक्षणिक संस्थानों के साथ उनकी बातचीत से इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति दिखी है।

श्री गोयल ने हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर कारीगरों को डिजिटल और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पहुंच प्रदान करने के लिए माल प्रबंधन में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) - माल को पटल पर लाने, प्रक्रिया डिजिटलीकरण और बाजार पहुंच सुगम बनाकर तथा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ समेकन सहित, सहयोग के लिए तत्पर है।

भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप परितंत्र का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि अभी इस क्षेत्र में 350 से अधिक स्टार्टअप संचालित हैं, जिनके मूल में डीप-टेक नवोन्मेष है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र दो अरब डॉलर से अधिक का बन चुका है और सरकार का आगामी वर्षों में कई यूनिकॉर्न कंपनियों (एक अरब डॉलर से अधिक कारोबार वाली कंपनियां) के उदय को बढ़ावा देने का लक्ष्य है।

संवाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया, विभाग के संयुक्त सचिव श्री संजीव, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बोट के सह-संस्थापक और मुख्य विपणन अधिकारी श्री अमन गुप्ता, ओयो रूम्स के संस्थापक और समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रितेश अग्रवाल और स्किनकेयर और हेयरकेयर कंपनी मिनिमलिस्ट के सह-संस्थापक श्री मोहित यादव मौजूद रहे।

श्री गोयल ने संवाद के समापन पर स्टार्टअप्स और छोटे उद्यमों को बड़े निवेशकों और निमार्ताओं से जोड़कर मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला निर्मित करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट इंडिया और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग जैसे संस्थान इसे सुगम बना रहे हैं ताकि स्टार्टअप्स को बाजार में मांग, पूंजी और विस्तार का लाभ मिल सके। उन्होंने उद्यमियों को उभरते अवसरों का पता लगाने, फायदे-नुकसान का आकलन करते हुए जोखिम उठाने और नवाचार आधारित विकास को तेज करने के लिए भारत की अद्वितीय प्रतिभाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया।

डीसीपीसी ने एसकेयूएएसटी-के में किसानों के लिए सुरक्षित कीटनाशक उपयोग और आईपीएम प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया

(जीएनएस)।

रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग (डीसीपीसी) की सचिव सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा ने कृषि की स्थिरता और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशकों के सुरक्षित और विनियमित उपयोग पर बल दिया है।

वो 12 जनवरी 2026 को श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एसकेयूएएसटी-के) में आयोजित एक दिन के किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थी। इसका विषय था "कीटनाशकों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग और एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) प्रथाओं को बढ़ावा देना।"

इस कार्यक्रम का समन्वय एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड और एसकेयूएएसटी-के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। डीसीपीसी सचिव ने एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड और एसकेयूएएसटी-के के सहयोगात्मक प्रयासों की सराहना की और कीटनाशकों के दुरुपयोग को कम करने के लिए किसानों के प्रशिक्षण, आईपीएम पद्धतियों को अपनाने और जागरूकता पैदा करने को प्रमुख रणनीतियों के रूप में रेखांकित किया।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के डीसीपीसी की सचिव सुश्री निवेदिता शुक्ला वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई । जबकि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

की अतिरिक्त सचिव डॉ. मनिंदर कौर द्विवेदी विशिष्ट अतिथि थीं। डीसीपीसी, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, यूएनआईडीओ, एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड, एसकेयूएएसटी-के और कश्मीर कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस कार्यक्रम में श्रीनगर और आसपास के जिलों के 524 किसानों ने उत्साहपूर्वक शामिल हुए। एक प्रमुख आकर्षण क्षेत्रीय सब्जी फसलों के लिए एक एकीकृत कीट प्रबंधन संकलन (आईपीएम) का शुभारंभ था । इसका उद्देश्य किसानों और विस्तार कार्यकताओं को सहयोग प्रदान करना था। श्रीनगर क्षेत्र के सोलह किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) ने शहद, केसर, खुबानी आधारित उत्पाद और मिर्च सहित स्थानीय उपज और मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रदर्शन किया।

कश्मीर क्षेत्र में जीईएफ/यूएनआईडीओ फार्म परियोजना (कृषि रसायन न्यूनीकरण और प्रबंधन के वित्तपोषण) के संयुक्त कार्यान्वयन के लिए एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड और एसकेयूएएसटी-के के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अनुकूलनशील आसियान: कनेक्टिविटी से संबद्ध बुद्धिमता तक' विषय पर छठी आसियान-भारत डिजिटल मंत्री बैठक संपन्न

बैठक में डिजिटल समावेशन और एकीकरण पर केंद्रित क्षेत्रीय डिजिटल सहयोग मजबूत करने के प्रति आसियान देशों और भारत की साझा प्रतिबद्धता को दोहराया गया

आसियान और भारत ने डिजिटल साझीदारी मजबूत करते हुए आसियान-भारत डिजिटल कार्य योजना 2026 को मंजूरी दी

भारत ने आसियान साझीदारों को लिए स्वदेशी और किफायती समाधानों के प्रस्ताव पर जोर दिया

भारत ने दूरसंचार उपयोगकताओं के बचाव और धोखाधड़ी रोकने के लिए 'संचार साथी' पहल को रेखांकित करते हुए आसियान साझीदारों के साथ सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों को साझा करने का प्रस्ताव रखा

(जीएनएस)।

आसियान और भारत के डिजिटल मंत्रियों (एडीजीएमआईएन) की छठी बैठक आज आभासी माध्यम से आयोजित की गई। इसमें आसियान के सदस्य देशों और भारत ने डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की साझा

प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के सचिव श्री अमित अग्रवाल तथा विएतनाम के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री गुयेन मान्ह हंग ने साथ मिल कर की।

एडीजीएमआईएन आसियान के 11 सदस्य देशों और संगठन के वार्ता साझीदार राष्ट्रों का एक वार्षिक मंच है। इसमें भाग लेने वाले आसियान के 11 सदस्य देश ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, मलेशिया, म्यांमार, फिलिपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, पूर्वी तिमोर और विएतनाम हैं। आसियान के वार्ता सहयोगियों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं। बैठक में क्षेत्रीय डिजिटल सहयोग मजबूत करने से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। बातचीत डिजिटल समावेशन और एकीकरण पर केंद्रित रही।

बैठक ने 10 अक्टूबर 2024 को वियनतियाने, लाओ जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य में आयोजित 21वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में 'डिजिटल परिवर्तन को आगे बढ़ाने पर आसियान-भारत संयुक्त वक्तव्य' को अपनाने पर सहमति हुई। इसका उद्देश्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, वित्तीय प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, एआई, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझाकरण और संवहनीय वित्तपोषण और निवेश पर आपसी सहयोग को मजबूत करना है। बैठक में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से 'आसियान-भारत 2025 डिजिटल कार्य योजना' में सहयोग गतिविधियों को लागू करने में हुई प्रगति पर भी विचार किया गया। इसके अतिरिक्त, बैठक में 2026 के लिए आसियान-भारत डिजिटल कार्य योजना का स्वागत किया गया, जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं: (i) आईसीटी (कउळ) प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रम; (ii) भारत-आसियान नियामक सम्मेलन और (iii) दूरसंचार सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समाधानों का उपयोग। बैठक में एक विशेष 'डिजिटल भविष्य के लिए आसियान-भारत कोष' के संचालन का भी स्वागत किया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए, श्री अमित अग्रवाल ने आसियान-भारत डिजिटल सहयोग के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता की पुष्टि की और 'अनुकूलनशील आसियानः कनेक्टिविटी से संबद्ध बुद्धिमता तक' विषय का स्वागत किया। उन्होंने कहा, 'हमने डिजिटल विभाजन को कम करने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सामूहिक रूप से कार्य किया है और सुनिश्चित किया है कि डिजिटल परिवर्तन समावेशिता, मजबूती और आर्थिक विकास के लिए एक ताकत के रूप में उभरे।

उन्होंने भारत के तीव्र डिजिटल परिवर्तन, सार्वभौमिक 4 जी कवरेज, दुनिया का सबसे तेज 5 जी रोलआउट, भारतनेट के माध्यम से विस्तारित ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और एक प्रमुख मोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत के उभरने पर प्रकाश डाला। इसके अलावा, उन्होंने समावेशी विकास और कुशल सेवा वितरण के लिए 'आधार' यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को समावेशी विकास और कुशल सर्विस डिलीवरी के लिए साबित प्लेटफॉर्म के तौर पर प्रस्तुत किया। भारत ने दूरसंचार उपयोगकर्ता की सुरक्षा और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए 'संचार साथी' पहल पर भी प्रकाश डाला और आसियान देशों के साथ बेहतरीन कार्यप्रणाली को साझा करने की पेशकश की।

कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) की परिवर्तनकारी भूमिका पर जोर देते हुए, भारत ने 'इंडिया एआई मिशन' की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें सुरक्षित और विश्वसनीय एआई पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही, भारत ने एआई के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, मानकों के विकास और व्यावहारिक उपयोग के मामलों पर आसियान देशों के साथ सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की। श्री अमित अग्रवाल ने कहा, 'जैसे-जैसे हम कनेक्टिविटी से बुद्धिमता की ओर बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक निर्णायक शक्ति होगी। भारत एआई पर एक स्पष्ट धारणा के साथ आगे बढ़ रहा हैः नवाचार को जिम्मेदारी, पारदर्शिता और जनता के भरोसे के साथ ही उपयोग करना चाहिए।

बैठक में पारस्परिक विकास और क्षेत्रीय समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए एक खुले, सुरक्षित, समावेशी और नवाचार-प्रेरित डिजिटल परिवेश के निर्माण के लिए भारत और आसियान के साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की गई।

भारत का कपड़ा और कपड़ों का एक्सपोर्ट दुनिया भर की मुश्किलों के बीच भी तेजी से बढ़ रहा है

बड़े पैमाने पर मार्केट में अलग-अलग तरह के लोग, वैल्यू एडिशन और खास पॉलिसी से जुड़े कदम सेक्टर की मजबूती को मजबूत करते हैं

अलग-अलग दुनिया के मार्केट में हैंडीक्राफ्ट, RMG और MMF सेगमेंट में अच्छे प्रदर्शन से दिसंबर 2025 में एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी

(जीएनएस)।

भारत के टेक्सटाइल और अपैरल (ळ&अ) एक्सपोर्ट ने ग्लोबल ट्रेड के खराब माहौल के बावजूद मजबूती और लगातार ग्रोथ दिखाई है, जो इस सेक्टर की एडजस्ट करने की क्षमता, अलग-अलग मार्केट में मौजूदगी और वैल्यू-एडेड और लेबर-इंटेंसिव सेगमेंट में मजबूती को दिखाता है। इस सेक्टर ने लगातार दूसरे महीने पॉजिटिव ग्रोथ दर्ज की, दिसंबर 2025 में एक्सपोर्ट दिसंबर, 2024 के मुकाबले 0.40% बढ़कर 3.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो नवंबर 2025 में अच्छी ग्रोथ के बाद हुआ।

दिसंबर 2025 के दौरान, एक्सपोर्ट ग्रोथ खास सेगमेंट में बड़े पैमाने पर रही, जिसमें हैंडीक्राफ्ट (7.2%), रेडीमेड गारमेंट्स (2.89%), और MMF यार्न, फैब्रिक और मेड-अप्स (3.99%) सबसे आगे रहे। ये ट्रेंड्स वैल्यू-एडेड मैन्युफैक्चरिंग, पारंपरिक क्राफ्ट्स और रोजगार देने वाले प्रोडक्शन में भारत के कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को दिखाते हैं, भले ही ग्लोबल डिमांड की स्थिति अस्थिर हो।

कैलेंडर-ईयर बेसिस (जनवरी-दिसंबर 2025) पर, टेक्सटाइल और कपड़ों का एक्सपोर्ट वरू 37.54 बिलियन पर स्थिर रहा, जिसमें हैंडीक्राफ्ट (17.5%), रेडीमेड गारमेंट्स (3.5%), और जूट प्रोडक्ट्स (3.5%) में कुल मिलाकर अच्छी ग्रोथ हुई। जियोपॉलिटिकल टेंशन और खास मार्केट में महंगाई के दबाव के बावजूद, इस पैमाने पर स्थिरता इस सेक्टर की स्ट्रक्चरल मजबूती और डायवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बास्केट को दिखाती है।

2025 की एक प्रमुख उपलब्धि उल्लेखनीय बाजार विविधीकरण रही है। जनवरी-नवंबर 2025 के दौरान, भारत के वस्त्र क्षेत्र ने 2024 की इसी अवधि की तुलना में 118 देशों और निर्यात गंतव्यों में निर्यात वृद्धि दर्ज की, जो बाजार प्रदर्शन में व्यापक सुधार को दशार्ता है। उभरते और पारंपरिक दोनों ही बाजारों में मजबूत विस्तार देखा गया, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात (9.5%), मिस्र (29.1%), पोलैंड (19.3%), सूडान (182.9%), जापान (14.6%), नाइजीरिया (20.5%), अर्जेंटीना (77.8%), कैमरून (152.9%) और युगांडा (75.7%) शामिल हैं, साथ ही स्पेन (7.9%), फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम जैसे प्रमुख यूरोपीय बाजारों में भी स्थिर वृद्धि दर्ज की गई।

यह विविधीकृत वृद्धि प्रवृत्ति भारत के वस्त्र निर्यात क्षेत्र की मजबूती और व्यापक गंतव्यों में भारत की वैश्विक बाजार उपस्थिति के सुदृढ़ होने को रेखांकित करती है।

यह सकारात्मक निर्यात प्रदर्शन एक सुव्यवस्थित नीतिगत ढांचे द्वारा और अधिक सशक्त किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करना और बाजार विस्तार करना है। समग्र रूप से, निरंतर निर्यात गति, विस्तृत होता बाजार दायरा और मूल्य-संवर्धित खंडों का मजबूत प्रदर्शन, वस्त्र और परिधान के लिए एक विश्वसनीय और लचीले वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में भारत की स्थिति की पुनः पुष्टि करता है। विविधीकरण, प्रतिस्पर्धात्मकता और एमएसएमई की भागीदारी पर निरंतर जोर के साथ, यह क्षेत्र आने वाले समय में निर्यात को और बढ़ाने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ अपने एकीकरण को गहरा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है।

जनजातीय चिकित्सकों का सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में एकीकरण: जनजातीय चिकित्सकों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय स्वास्थ्य रूपांतरण में जनजातीय चिकित्सकों को भागीदार बनाया

भारत को पहली राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला मिलेगी, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भुवनेश्वर स्थित आईसीएमआर-आरएमआरसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

(जीएनएस)।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 16 जनवरी 2026 को हैदराबाद के कान्हा शांति वनम ू२७ जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए जनजातीय चिकित्सकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में जनजातीय चिकित्सकों को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने एवं उन्हें सहयोगी भागीदार के रूप में शामिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय पहल है, जो प्रधानमंत्री के समावेशी, अंतिम-मील और समुदाय-नेतृत्व के माध्यम से एक विकसित भारत के निर्माण वाले दृष्टिकोण के अनुरूप है।

उद्घाटन सत्र में जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम; जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुगार्दास उइके; तेलंगाना के जनजातीय कल्याण मंत्री श्री अदलुरी लक्ष्मण कुमार; महबूबाबाद के सांसद श्री बलराम नाइक; भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी; प्रमुख चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि; राज्य सरकार के अधिकारी; और पुरे देश से लगभग 400 जनजातीय चिकित्सक उपस्थित हुए।

सभा को संबोधित करते हुए श्री मनीष ठाकुर, अतिरिक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने कहा कि जनजातीय चिकित्सकों को उनके समुदायों में पीढ़ियों से विश्वास एवं सामाजिक मान्यता प्राप्त है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) अब जनजातीय चिकित्सकों को अपने स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोगी भागीदार के रूप में देखता है, विशेष रूप से निवारक देखभाल, बीमारी की शीघ्र पहचान और समय पर परामर्श जैसे क्षेत्र में। उन्होंने कहा कि भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं प्रणालीगत बाधाएं जनजातीय समुदायों की औपचारिक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सीमित करती है जबकि विश्वसनीय चिकित्सकों की सक्रिय भागीदारी अंतिम-मील तक सेवा वितरण को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर सकती है।

श्रीमती रंजना चोपड़ा, सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने समुदाय-आधारित और समुदाय-प्रधान स्वास्थ्य समाधानों को मुख्यधारा में लाने में जनजातीय चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दृष्टिकोण लागत-कुशल, स्थायी एवं स्थानीय वास्तविकताओं पर आधारित होते हैं। कई जनजातीय जिलों में मलेरिया, तपेदिक और कुष्ठ जैसी संक्रामक बीमारियों की लगातार प्रचलित स्थिति को उजागर करते हुए उन्होंने इन रोगों को उन क्षेत्रों से समाप्त करने के लिए अंतिम एवं लक्षित प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया।

ओडिशा, महाराष्ट्र और राजस्थान के जनजातीय चिकित्सकों के साथ अपने संवाद के दौरान, सचिव ने सम्मान एवं औपचारिक मान्यता, पारंपरिक ज्ञान का पीढ़ीगत हस्तांतरण सुनिश्चित करने वाले तंत्र और दुर्लभ औषधीय पौधों और जड़ी-बूटियों के संरक्षण के लिए उनकी आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रीत किया। उन्होंने जानकारी दी कि मंत्रालय ने जनजातीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में साझेदार के रूप में एक लाख जनजातीय चिकित्सकों को औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान करने एवं सक्षम बनाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

श्री बालराम नायक, महबूबाबाद, तेलंगाना के सांसद ने कहा कि जीवनशैली से जुड़े कारणों, जैसे तंबाकू सेवन के कारण जनजातीय समुदायों में तपेदिक जैसी बीमारियां प्रचलित है।

वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय प्रदर्शनी-2026 में स्वास्थ्य मंडप का सशक्त जनभागीदारी और सकारात्मक प्रभाव के साथ सफल समापन

(जीएनएस)।

गुजरात के राजकोट में मारवाड़ी विश्वविद्यालय में 11 से 15 जनवरी 2026 तक आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल एग्जिबिशन (वीजीआरई) 2026 का समापन भारत और विदेश से आए आगंतुकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ हुआ। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने हॉल संख्या 6 में एक व्यापक स्वास्थ्य पवेलियन के माध्यम से प्रदर्शनी में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई।

लगभग 700 वर्ग मीटर में बनाया गया यह स्वास्थ्य मंडप "स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत" की थीम पर आधारित है और इसमें भारत सरकार के जन स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के जन-केंद्रित दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया। इस मंडप का उद्घाटन 11 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों और जिला स्वास्थ्य एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

इस पवेलियन में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 12 कार्यक्रम विभागों के 26 स्टॉल लगाए गए थे जिनमें राज्य सरकार और जिला स्वास्थ्य एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी रही। पांच दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान, पवेलियन ने आम जनता के लिए व्यापक स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, जांच, परामर्श और जागरूकता गतिविधियां प्रदान कीं। इनमें एचआईवी और मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श; आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), फ्लोरोसिस की रोकथाम, ईट राइट इंडिया, वन हेल्थ और भारत में स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी मूल्यांकन पर जागरूकता सत्र के साथ ही रक्तचाप, रक्त शर्करा, रक्त समूह, मुख कैंसर, नेत्र और कान के स्वास्थ्य की जांच भी शामिल थी। वृद्धावस्था संबंधी आकलन और बुनियादी वृद्धावस्था पुनर्वास से संबंधित सेवाएं भी प्रदान की गईं।

नैदानिक और सूचनात्मक सेवाओं के अलावा, इस पवेलियन में निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई आकर्षक पहुंच गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें गुजरात सरकार की तपेदिक और टीकाकरण टीमों द्वारा नुक्कड़ नाटक प्रदर्शन, नजफगढ़, नई दिल्ली स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र द्वारा लाइव सीपीआर प्रदर्शन और पुरस्कार वितरण के साथ स्वास्थ्य संबंधी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शामिल थी। आगंतुकों, विशेष रूप से बच्चों को आकर्षित करने और स्वस्थ मनोरंजन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पारंपरिक, स्क्रीन-मुक्त खेलों के लिए एक विशेष स्थल भी बनाया गया था।

स्वास्थ्य मंडप को विदेशी नागरिकों सहित आगंतुकों से जबरदस्त और उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और यह वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय प्रदर्शनी 2026 के प्रमुख आकर्षणों में से एक बनकर उभरा। मजबूत जनभागीदारी ने सरकारी स्वास्थ्य पहलों के प्रति बढ़ती जागरूकता और विश्वास को दर्शाया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों की व्यापक पहुंच और प्रभाव को उजागर किया।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सतत नवाचार, राज्यों और हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रयासों और देश भर में समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहलों के निरंतर कार्यान्वयन के माध्यम से "स्वस्थ भारत, श्रेष्ठ भारत" की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

नवसारी मनपा के बाहरी क्षेत्रों में 112 करोड़ रुपये के खर्च से बनने वाले जलापूर्ति एवं ड्रेनेज नेटवर्क से 25 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे

नवसारी में नए ड्रेनेज और जलापूर्ति नेटवर्क से पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से मिलेगी राहत

गुजरात सरकार का जल प्रबंधन के कार्यों से छोटे शहरों को समस्याओं से मुक्त करने का अर्बन विजन

गांधीनगर, 16 जनवरी : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार शहरीकरण को गति देने के साथ-साथ नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग यानी जीवन सुगमता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार शहरों के विस्तार के साथ ही नए शामिल होने वाले क्षेत्रों में जलापूर्ति, ड्रेनेज पाइपलाइन, सड़क एवं स्वच्छता जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। इसके अंतर्गत हाल ही में नवसारी महानगर पालिका ने 112 करोड़ रुपए की जलापूर्ति और ड्रेनेज परियोजना कार्यान्वित की है।

उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी, 2025 को नवसारी महानगर पालिका का गठन किया गया था, जिसमें पहले के नवसारी विजलपोर नगर पालिका क्षेत्र के साथ 4 निकटवर्ती गांवों एरु, धारागीरी, दांतेज और हांसापोर को शामिल किया गया। शहर के इन बाहरी इलाकों में शुद्ध पेयजल और ड्रेनेज की लाइनों के अभाव के कारण पीने के पानी और ड्रेनेज की गंभीर समस्या थी। इन समस्याओं के स्थायी हल के लिए नवसारी महानगर पालिका द्वारा इन क्षेत्रों में लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत से एक नया जलापूर्ति और ड्रेनेज नेटवर्क बनाया जा रहा है।

112 करोड़ रुपए के खर्च से बनने वाले नए ड्रेनेज नेटवर्क से 25 हजार से अधिक लोग लाभान्वित होंगे

इस परियोजना के अंतर्गत महानगर पालिका द्वारा चरणबद्ध तरीके से नई पानी और ड्रेनेज की पाइपलाइनें, ओवरहेड टंकी और भूमिगत सम्प, ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी), नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी आधुनिक ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे 25,000 से अधिक स्थानीय नागरिकों को पेयजल और गंदे पानी की निकासी की समस्या से बड़ी राहत मिलेगी। विशेषकर, बच्चों में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का भी अंत आएगा।

नवसारी में जलापूर्ति और नया ड्रेनेज नेटवर्क केवल ढांचागत सुविधाओं में ही सुधार नहीं करेगा, बल्कि यह शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित होगा। नवसारी मनपा क्षेत्र में शामिल किए गए चार गांवों में सड़क, लाइट, ड्रेनेज और पानी के नए नेटवर्क के अलावा उद्यान और तालाबों का विकास कर विहार धाम का निर्माण, सिविक सेंटर और सफाई के लिए डस्टबिन वितरण का भी आयोजन किया जा रहा है।

नवसारी महानगर पालिका के आयुक्त श्री देव चौधरी ने इस परियोजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 'नए साल में नवसारी महानगर पालिका शहर में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। जिसमें ड्रेनेज, सड़कें, स्टॉर्म वाटर और पानी की व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसी उद्देश्य से शहर में शामिल किए गए चार गांवों में ड्रेनेज, पानी और स्टॉर्म वाटर का समग्र नेटवर्क बिछाने की योजना बनाई गई है। पहले चरण में इन चार गांवों में ड्रेनेज और जलापूर्ति का काम किया जाएगा। यह परियोजना निर्धारित समयरेखा के अनुसार क्रियान्वित की जा रही है, जिससे लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी और उनकी सुख-सुविधा में वृद्धि होगी।'

गुजरात की विकास यात्रा में मील का पत्थर बना 'शहरी विकास वर्ष'

वर्ष 2005 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार 'शहरी विकास वर्ष' मनाने की शुरूआत की थी और शहरी विकास के प्रयासों को और मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें शुरू की थीं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल भी श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस विकास यात्रा को गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यही कारण है कि उन्होंने 20 वर्ष बाद, 2025 को एक बार फिर 'शहरी विकास वर्ष' के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

हरिद्वार : विजिलेंस की कार्रवाई से हड़कंप, जिला पूर्ति अधिकारी राशन डीलर से 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार

(जीएनएस)।

उत्तराखंड में एक बार फिर विजिलेंस की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पूर्ति विभाग में रिश्वतखोरी का खुलासा किया है। विजिलेंस ने हरिद्वार जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य और उनके सहायक गौरव शर्मा रिश्वत लेते हुए पकड़ा है।

जिला पूर्ति कार्यालय परिसर में ही विजिलेंस टीम ने दबिश देकर दोनों को रंगे हाथ दबोचा। दोनों आरोपियों को 50 हजार की रिश्वत लेते समय पकड़ा गया। जिला पूर्ति अधिकारी पर राशन डीलर से काम के बदले 50 हजार की रिश्वत लेने का आरोप लगा है।

पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस ने सुनियोजित तरीके से जाल बिछाकर कार्रवाई अंजाम दिया। रिश्वत की पूरी रकम मौके से बरामद की गई है। विजिलेंस की टीम ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। विजिलेंस की छापेमारी से पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। विजिलेंस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

विजिलेंस के अनुसार टीम ने हरिद्वार के जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य एवं उनके एक सहायक को 50000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। जिला पूर्ति कार्यालय में ही विजिलेंस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पीड़ित की शिकायत पर विजिलेंस ने जाल बिछाया।

पीड़ित ज्वालापुर स्थित तहसील में जिला पूर्ति कार्यालय में पहुंचा तो विजिलेंस की टीम पहले ही तैयारी में थी। उसने रिश्वत के रुपए दिए तो तत्काल विजिलेंस ने जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य और उनके सहायक गौरव शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए भ्रष्टाचार के तौर पर वसूली गई रकम भी बरामद कर ली। दोनों से पूछताछ जारी है, इसके बाद देहरादून ले जाया जाएगा।

दोनों की संपत्तियों का भी ब्यौरा जुटाया जा रहा है। हाल ही में विजिलेंस ने खंड शिक्षा अधिकारी बहादराबाद बृजपाल की राठौर, उनके सहायक को भी विजिलेंस की टीम ने ₹20000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। हरिद्वार में बड़े और भ्रष्ट्राचारी अफसरों पर विजिलेंस का एक्शन जारी है।

साहित्य अकादमी ने नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला-2026 में फेस-टू-फेस और कहानी पठन कार्यक्रमों का आयोजन किया

(जीएनएस)।

साहित्य अकादमी ने 15 जनवरी 2026 को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के दौरान हॉल नंबर 2, भारत मंडपम, नई दिल्ली में भारत की बौद्धिक परंपराओं पर एक फेस-टू-फेस कार्यक्रम और एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।

फेस-टू-फेस कार्यक्रम में प्रख्यात मलयालम लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता श्री केपी रामानुन्नी ने भाग लिया और अपने साहित्यिक जीवन और कार्यों से जुड़े अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि वे कोझिकोड शहर से हैं, जिसे यूनेस्को द्वारा भारत का पहला और एकमात्र साहित्य नगर घोषित किया गया है। सत्र के दौरान, उन्होंने अपनी मलयालम लघु कहानी 'एमटीपी' (गभार्धान की चिकित्सा पद्धति) के कुछ अंश पढ़े, जिसका अंग्रेजी अनुवाद अबू बकर काबा ने किया है। नाटक के रूप में लिखी गई और सात भागों में विभाजित यह कहानी, लेखक के अपने जीवन के अनुभवों से प्रेरित होकर, गर्भपात की चिकित्सा प्रक्रिया से जुड़े गहन मानवीय नाटक का चित्रण करती है। अपने साहित्यिक सफर पर विचार करते हुए, श्री रामानुन्नी ने अपने प्रारंभिक वर्षों के बारे में बताया कि किशोरावस्था में वे एक साथ आध्यात्मिक और साम्यवादी साहित्य पढ़ रहे थे, जिससे उन्हें आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा और उन्होंने मनोचिकित्सक से परामर्श लिया। हालांकि यह उपचार निरर्थक साबित हुआ, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें लेखन के माध्यम से सुकून और अभिव्यक्ति पाने के लिए प्रेरित किया।

फेस-टू-फेस कार्यक्रम के बाद भारत की बौद्धिक परंपराओं पर एक पैनल चर्चा हुई, जिसमें प्रो. रवैल सिंह, प्रो. हरेकृष्ण सतपथी और प्रो. बसवराज कालगुडी ने भाग लिया। श्री रवैल सिंह ने पंजाब की बौद्धिक विरासत पर चर्चा करते हुए तक्षशिला के प्राचीन शिक्षा केंद्र से लेकर नाथ योगी, सूफीवाद और सिख धर्म तक के इतिहास का वर्णन किया। प्रो. हरेकृष्ण सतपथी ने प्राचीन और समकालीन शिक्षा प्रणालियों की तुलना करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महेश को आदिगुरु बताया और वेदों का एक श्लोक सुनाया। प्रो. बसवराज कालगुडी ने परिधीय ज्ञान प्रणालियों पर बात करते हुए, उन्हें मौखिक और लिखित परंपराओं में वर्गीकृत किया और प्राचीन भारत में जनजातीय और कृषि संबंधी ज्ञान परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डाला।

दोनों कार्यक्रमों को दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया, जिनमें विद्यार्थी, शिक्षक, लेखक और साहित्य प्रेमी शामिल थे, और इनमें सार्थक संवाद और चर्चा देखने को मिली। साहित्य अकादमी की ओर से सहायक संपादक डॉ. संदीप कौर ने धन्यवाद प्रस्ताव दिया।

मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करने और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए मत्स्य पालन सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया

'समय पर कार्रवाई, मजबूत कार्यान्वयन और वैज्ञानिक योजना आने वाले वर्षों में भारत के मत्स्य पालन विकास की दिशा तय करेगी': डॉ. अभिलक्ष लिखी

(जीएनएस)।

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग ने केंद्रीय मत्स्य पालन सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मत्स्य पालन सचिव सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (ढटटर), मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (ऋऋउऋ), और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (ढट-टडरर) के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही समुद्री मत्स्य पालन गणना 2025, मूल्य वर्धित समुद्री खाद्य निर्यात और विभिन्न योजनाओं के प्रमुख लक्ष्यों पर भी अद्यतन जानकारी दी गई। यह सम्मेलन एपी शिंदे संगोष्ठी हॉल, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, पूसा रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया गया।

इस सम्मेलन में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आईसीएआर संस्थानों, स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम (ऋऋअउ), नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ठउऊउ), नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ठअऋझऊ), मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (टढएऊअ) और अन्य क्षेत्रों के हितधारकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने फंड के इस्तेमाल के अहम मुद्दे पर जोर दिया। उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से मंजूर गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड को समय पर और कुशलता से बांटने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इंटीग्रेटेड एक्वापार्क, समुद्री शैवाल की खेती, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेजेज (CRCFVs), आर्टिफिशियल रीफ और क्लस्टर डेवलपमेंट के विकास के लिए समयबद्ध दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया।

डॉ. लिखी ने डिजिटलीकरण पर जोर देने का आ'ान किया, और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से नेशनल फिशरीज डिजिटल पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या बढ़ाने का आग्रह

किया। उन्होंने एक्वाकल्चर बीमा कवरेज में मौजूदा कमियों की जानकारी दी और मछुआरों की आजीविका की सुरक्षा के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसे ज्यादा से ज्यादा अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम धन धान्य योजना के तहत मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर घटकों पर बारीकी से नजर रखने की सलाह दी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के लाभ जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से पहुंचाए जाएं।

मत्स्य पालन विभाग के संयुक्त सचिव (इनलैंड) श्री सागर मेहरा ने इनलैंड मत्स्य पालन का अवलोकन किया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नीतिगत अधिसूचनाओं के बावजूद जलाशय मत्स्य पालन और इनलैंड क्लस्टर अविकसित हैं। उन्होंने बाजार से जुड़ी, उच्च मूल्य वाली प्रजातियों को बढ़ावा देकर और इनलैंड राज्यों के बीच निर्यात की तैयारी को मजबूत करके भारतीय मेजर कार्प्स से परे विविधीकरण की जरूरत पर जोर दिया।

मत्स्य पालन विभाग की संयुक्त सचिव (मरीन) सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद ने तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने मैरीकल्चर डेवलपमेंट (2025) के लिए एसओपी को जल्द से जल्द लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साफ समुद्री जल लीजिंग नियमों, बायोसिक्योरिटी प्रोटोकॉल और आसान अप्रूवल के साथ राज्य मैरीकल्चर नीतियों को अधिसूचित करने का आ'ान किया। उन्होंने बताया कि भारत की लंबी तटरेखा होने के बावजूद, खारे पानी के संसाधनों का केवल छोटा सा हिस्सा ही अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिनफिश, शेलफिश, कटलअ, समुद्री शैवाल और खुले समुद्र में केज फार्मिंग में विविधता लाने का आग्रह किया। उन्होंने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने और बाद में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सौर सुखाने और हरित ईंधन जैसी जलवायु-अनुकूल तकनीकों को अपनाने पर भी जोर दिया।

एमपीईडीए अध्यक्ष श्री डोड्डा वेंकट स्वामी ने वैल्यू-एडेड सीफूड निर्यात में अवसरों पर प्रस्तुति दी। इसमें वैश्विक बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए बेहतर कौशल विकास, मछली-अपशिष्ट के उपयोग और स्थिरता, बायोसिक्योरिटी और ट्रेसबिलिटी पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

आईसीएआर के उप महानिदेशक डॉ. जे.के. जेना ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आईसीएआर की अपेक्षाओं की जानकारी दी। इसमें कैच-डेटा संग्रह के लिए समान तकनीक अपनाने, मजबूत स्टॉक-मूल्यांकन प्रणालियों, न्यूनतम कानूनी आकार मानदंडों का पालन और प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के व्यापक प्रसार के लिए मल्टीप्लायर इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया गया।

एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी डॉ. बिजय कुमार बेहरा ने चर्चाओं के लिए रणनीतिक संदर्भ तय किया। इसमें सार्वजनिक निवेश के पैमाने का आकलन करने, प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने और वैल्यू-चेन इंटीग्रेशन में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और एक समय-सीमा वाला एक्शन प्लान विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लेखा नियंत्रक श्री सुभाष चंद्र ने केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत फंड जारी करने के बारे में जानकारी दी। इन योजनाओं में ढटटर भी शामिल है।

कउअफ-उटऋऋक निदेशक डॉ. ग्रिंसन जॉर्ज ने समुद्री मत्स्य गणना 2025 पर अपडेट साझा किए। इसमें पोर्टल सिंक्रोनाइजेशन, टेम्प्लेट सारांश रिपोर्ट को अंतिम रूप देना, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ऋकडेटा का इंटीग्रेशन और कच्चे डेटा को राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन डेटाबेस में बदलने की प्रक्रिया शामिल है।

उद्योग प्रस्तुतियों में सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों की जानकारी दी गई। श्री अर्जुन गाडरे (गाडरे मरीन एक्सपोर्ट) ने सुरिमी उत्पादों की सफलता की कहानी साझा की और वैल्यू-एडेड समुद्री भोजन के लिए बढ़ती घरेलू और वैश्विक मांग की रूपरेखा बताई। उन्होंने राज्यों से ऐसे उपाय लागू करने का आग्रह किया जो कच्चे माल की गुणवत्ता और प्रसंस्करण उत्कृष्टता सुनिश्चित करें, जो अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रों के लिए आवश्यक हैं।

इंडिया एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), और आईआईटी हैदराबाद ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन कार्य समूह बैठक की मेजबानी की

इंडिया एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (टीइ), और आईआईटी हैदराबाद ने सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन कार्य समूह बैठक की मेजबानी की समावेशी, मानव-केंद्रित और जिम्मेदार एआई अपनाने को बढ़ावा देना कार्य समूह की चर्चाओं से इंडिया एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 की जानकारी मिलेगी

(जीएनएस)।

इंडिया ए आई मिशन, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से आज आईआईटी हैदराबाद परिसर में सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेशन पर कार्य समूह बैठक की मेजबानी की।

इस बैठक में वरिष्ठ नीति निमार्ता, शैक्षणिक नेता, उद्योग विशेषज्ञ और शोधकर्ता एकत्र हुए ताकि समावेशी एआई विकास, एआई की सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ाने और एआई द्वारा संचालित अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर राष्ट्रीय चर्चाओं को आगे बढ़ाया जा सके।

यह बैठक इंडिया ए आई प्रभाव सम्मेलन 2026 का अग्रदूत है, जिसका आयोजन 16-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाला है। और यह पूरे देश में आयोजित की जा रही कार्य समूह परामर्श श्रृंखला का भी हिस्सा है ताकि शिखर सम्मेलन की विषयगत एजेंडा और परिणामों को जानकारी प्रदान की जा सके।

उद्घाटन सत्र में कार्य समूह के भारतीय अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव; राजदूत थॉमस श्नाइडर, स्विट्जरलैंड के संघीय संचार कार्यालय के निदेशक; प्रो. बी.एस. मूर्ति, आईआईटी हैदराबाद के निदेशक; डॉ. नलिन कुमार श्रीवास्तव, टीइ के एआई एवं ईटी डिवीजन के अतिरिक्त निदेशक; तथा श्री ची. भारत रेड्डी, तेलंगाना सरकार के संयुक्त निदेशक (ई-गवर्नेंस) के उद्बोधन हुए। सभी वक्ताओं ने भारत की एआई यात्रा के केंद्र में समावेशन, विश्वास और सामाजिक संदर्भ को स्थापित करने के महत्व पर बल दिया।

प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, आईआईटी हैदराबाद के निदेशक प्रो. बी.एस. मूर्ति ने कहा, 'यदि भारत वास्तव में एआई में नेतृत्व करना चाहता है, तो हमें साहसिक कदम उठाने होंगे। एआई

को बहु-विषयी होना चाहिए, जो इंजीनियरिंग, पदार्थ विज्ञान, उदार कला और इससे आगे सभी को एक साथ लाए। मजबूत आधारभूत सिद्धांतों से लेकर वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों तक, हमारा ध्यान जीवन को बेहतर बनाने पर होना चाहिए, साथ ही जिम्मेदार और स्वीकार्य एआई की चुनौतियों का समाधान भी करना चाहिए।'

कार्य समूह के लिए संदर्भ निर्धारित करते हुए, टीइ के एआई एवं ईटी डिवीजन के अतिरिक्त निदेशक श्री डॉ. नलिन कुमार श्रीवास्तव ने कहा, 'यह सभा समावेशन, पहुंच, जिम्मेदारी और एआई में समानता के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रज्वलित मन को एक साथ लाती है। यह केवल प्रौद्योगिकी के बारे में नहीं है, यह सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में है, जिसमें लोग केंद्र में हैं। एआई कोई प्रौद्योगिक विकल्प नहीं है, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है।'

अपने मुख्य उद्बोधन में, महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने जोर दिया, 'भारत का एआई पर कार्य कुल सात मेरुदंड(वर्टिकलस) के इर्द-गिर्द संरचित है, जिनमें से एक सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है, जिसमें कई देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों की सक्रिय भागीदारी है। जबकि एआई विज्ञान, सामग्री, स्वास्थ्य सेवा और शोध में प्रगति को सक्षम कर रहा है, जिसका अंतिम मकसद विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों की सेवा करना है।

भारत ने मजबूत डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया है, और इसका अगला कदम इन प्रणालियों में एआई परत जोड़ना है। जैसे-जैसे एआई बढ़ेगा, इसे सभी के लिए काम करना चाहिए, डेटा और भाषा में पूर्वाग्रह को संबोधित करना चाहिए, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रौद्योगिकी असमानताओं को न बढ़ाए बल्कि समाज के सभी वर्गों की मदद करे।'

तेलंगाना सरकार के संयुक्त निदेशक (ई-गवर्नेंस) श्री ची. भारत रेड्डी ने तेलंगाना सरकार के नवाचार पर महत्व दिए जाने के बारे में बात की और कहा, 'हमारा ध्यान हमेशा विकास पर रहा है, और नई प्रौद्योगिकियों का अपनाना उस उद्देश्य का केंद्रीय हिस्सा है। मैं तेलंगाना सरकार का प्रतिनिधित्व करता हूं, और ये प्रयास मजबूत, भविष्य-तैयार नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। दिल्ली में आगामी इंडिया एआई प्रभाव सम्मेलन में, इन विषयों को केंद्रित ब्रेकआउट सत्रों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा, जो इसके विभिन्न हितधारकों के बीच गहन चर्चा और सहयोग को सक्षम बनाएंगे।'

मुख्य उद्बोधन देते हुए, स्विट्जरलैंड के संघीय संचार कार्यालय के निदेशक राजदूत थॉमस श्नाइडर ने उजागर किया, 'एआई का उपयोग सतत तरीके से किया जाना चाहिए ताकि हम अपने ग्रह को ऐसी स्थिति में रख सकें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारा घर बना रहे। एआई का उपयोग प्रगति के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें आर्थिक और सामाजिक विकास शामिल है, और एआई तथा डेटा द्वारा प्रदान किए गए अवसरों को आज लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को पार करने के लिए हथियाया जाना चाहिए।

यह प्रगति केवल कुछ के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए होनी चाहिए, वह भी लोगों की गरिमा, मौलिक अधिकारों और स्वायत्तता का सम्मान करते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई पीछे न छूटे। जब इसे जिम्मेदारीपूर्वक डिजाइन कर तैनात किया जाए, तो एआई भलाई के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है। लेकिन हमें पूर्वाग्रह, असमानता और बहिष्कार के खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। समावेशी, बहुपक्षीय और बहु-हितधारक सहयोग एआई की तरफ से सामान्य हित की सेवा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसी भावना में, एआई के माध्यम से समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन होना चाहिए। यह एआई को सभी के लिए अवसर बनाने और कुछ के लिए विशेषाधिकार न बनाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

'कार्यक्रम 'एआई के साथ भारत की पुनर्कल्पना' शीर्षक मुख्य उद्बोधन में परिवर्तित हो गया, जिसे रिलायंस जियो के मुख्य डेटा वैज्ञानिक प्रो. शैलेश कुमार ने प्रस्तुत किया। इसमें राष्ट्रीय विकास को स्केल करने में नवाचार की भूमिका की जांच की गई। इसके बाद 'समावेशी एआई विकास को बढ़ावा देने' पर पहली पैनल चर्चा हुई, जिसमें प्रो. सुमोहना चन्नप्पय्या (आईआईटीएच); श्री रोमी श्रीवास्तव, हनीवेल; श्री स्वरूप शांति मेदासनी (मैथवर्क्स); श्री रामिया कन्नन बाबू (इंटेल) और प्रो. चक्रवर्ती भगवती (हैदराबाद विश्वविद्यालय) की भागीदारी रही।

विशेषज्ञों ने एआई जीवनचक्र में समावेशिता को कैसे अंतर्निहित किया जा सकता है—प्रारंभिक डेटा संग्रह और डिजाइन से लेकर तैनाती और शासन तक में इसका उपयोग कैसे हो, इसकी प्रस्तुति दर्शाई ।

पैनलिस्टों ने अनुसंधान और उद्योग अनुभव पर आधारित होकर, पूर्वाग्रह को कम करने, पहुंच का विस्तार करने और सामाजिक तथा आर्थिक समावेशन को आगे बढ़ाने वाले एआई प्रणालियों के निर्माण की साझा जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों पर चर्चा की।